



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

695] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 1990/अग्रहायण, 6, 1912  
No. 695] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 1990/AGRAHAYANA, 6, 1912

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

---

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1990

का. आ. 915(अ):— यतः यूनाइटेड निवेशन फंड आफ असम तथा उसके  
वर्धन घटकों, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उलका कहा गया है, का घोषित उद्देश्य असम का  
भारत से घ से मुक्त कराना और इस प्रकार असम को भारत संघ से अलग करना है ;

और यतः उल्फा, लोगों में असुरक्षा की गहरी भावना पैदा करने, और घन गैठने, राजनीतिक नेताओं, पुलिस अधिकारियों, व्यापारियों तथा अन्य लोगों की हत्याएँ करने, लोगों को डराने, धमकी देने, अपहरण करने तथा परेशान करने, लार्डसेंस धारियों से उनके आने-यात्रे छीनने, उर्कतिया डालने, राज मार्गों पर लूटपाट करने और बैंकों को लूटने, सामाजिक तथा आर्थिक अपराधों के कथित दोषी व्यक्तियों को सजा देने और भूमि और भवनों पर जबरन कब्जा करने जैसे अन्य अपराध करते हुए ऐसी विभिन्न विधि विरुद्ध तथा हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त रहा है उनका आशय भारत की सम्प्रभुता और अखंडता का छिन्न-भिन्न करना है या जिनसे भारत की प्रभुता और अखंडता छिन्न-भिन्न होती है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह मत है कि उल्फा एक विधि विरुद्ध संगठन है ;

अतः अब विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) को एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित करती है।

केन्द्रीय सरकार का आगे यह मत है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अर्थात् उल्फा द्वारा हाल ही में पुलिस, अन्य सशस्त्र बलों तथा नागरिकों के खिलाफ की जा रही लगातार तथा बढ़ती हुए हिंसा का मुकाबला करने के लिए उल्फा का, तत्काल प्रभावी रूप से, एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त धारा की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी आदेश के अन्वय में रहते हुए, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 11011/109/90 एन ई—IV]

विनय शर्मा, सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1990

S.O. 915(E).—Whereas the United Liberation Front of Assam and the various wings thereof, hereinafter referred to as ULFA, have as its professed aim, the “liberation” of Assam from the Indian Union and thereby, the secession of Assam from the Indian Union ;

And whereas ULFA has been indulging in various illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the sovereignty and integrity of India,

such as by creating a deep sense of insecurity among the people, and by committing other acts like extortion of money, murders of political leaders, police officials, businessmen and others, threat, intimidation, kidnapping and harassment of people, snatching of fire arms from licence holders, dacoities, highway robberies and looting of banks, punishment of alleged offenders for social and economic crimes and forcible occupation of lands and buildings ;

And whereas the Central Government is of the opinion on the materials before it that ULFA is an unlawful association ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the United Liberation Front of Assam (ULFA) to be an unlawful association.

The Central Government is further of opinion that having regard to the circumstances namely, to meet the sustained and ever increasing violence committed by the ULFA in the recent past against the police, the other armed forces and the civilians, it is necessary to declare the ULFA an unlawful association with immediate effect, and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 11011/109/90-NE IV]  
VINAY SHANKAR, Jt. Secy.

